भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी)

केन्द्रीय कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति 20 नवंबर, 2021

मोदी का सिर झुकाकर कृषि कानूनों को रद्द करवाने वाले भारत के किसानों की जय–जयकार!

साम्राज्यवादियों, बहुराष्ट्रीय निगमों, भारत के दलाल नौकरशाही पूंजीपतियों के हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए कृषि कानूनों के रद्द के लिए विगत साल भर से लाखों किसानों ने दिल्ली में धरना देते हुए आखिर जीत हासिल की. इस घमंड के साथ कि उनका कोई सामना नहीं कर सकता है, संसद में उनकी पार्टी को प्राप्त बहुमत के चलते वो कुछ भी कर सकते हैं, अत्यंत निरंकुश तरीके से सितंबर 2020 में बनाए गए तीन कृषि कानूनों को आगामी नवंबर महीने की आखिरी में होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में वापस लेने की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर के दिन राष्ट्र के नाम एक विशेष संबोधन में घोषणा की. यह भारत के किसानों के संघर्ष की जीत है. साल भर से दिल्ली में कई कठिनाइयों व नुकसानों को झेलते हुए अपनी जायज मांगों को हासिल करने आंदोलन को जारी रखने वाले अन्नदाताओं के समर्थन में समूचा देश खड़ा था. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के किसानों के प्रति अभूतपूर्व भाईचारा प्रकट हुआ. इस तरह यह जीत देश की जनता की है. निरंकुश कृषि कानूनों के रद्द के लिए पिछले साल भर से लड़ते हुए करीबन 700 किसानों ने अपनी जानें गंवायी. पहले उन सभी को हमारी केंद्रीय कमेटी क्रांतिकारी जोहार अर्पित करती है. केंद्र सरकार का सिर झुकाकर कृषि कानूनों को रद्द करने उसे मजबूर करने के अवसर पर 26 नवंबर को विजय दिवस मनाने हमारी केंद्रीय कमेटी देश के किसानों का आह्वान करती है.

हमारे देश के इतिहास में अभूतपूर्व ढंग से सैकड़ों किसान संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसाना मोर्चे का गठन कर उसके नेतृत्व में समझौताविहीन व उज्वल आंदोलन को संचालित किया. उनके संघर्ष पर पानी फेरने हिंदुत्व शक्तियों ने कई षड्यंत्र किए. उन पर कई हमले किए. फिर भी, उनकी परवाह किए बगैर संघर्ष के पथ पर दृढ़तापूर्वक डटे रहकर उन्होंने मोदी सरकार को करारा जवाब दिया. वर्तमान किसान आंदोलन की जीत इस बात का एक और बड़ा उदाहरण है कि केंद्र की ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी भाजपा सरकार द्वारा अपनायी जा रही तमाम जन विरोधी नीतियों का देश की जनता कड़ा विरोध कर रही है. इस आंदोलन ने एक बार और जनता के सामने विश्वासभरा यह संदेश रखा कि संघर्षों के जरिए ही ब्राह्मणीय हिंदुत्व शक्तियों की जनविरोधी नीतियों को परास्त कर सकते हैं.

यह विदित है कि देश की जनता के व्यापक विरोध के कारण मोदी को उनकी सरकार द्वारा 2015 में लाए गए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को वापस लेना पड़ा. उसी तरह मार्च 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि एससी, एसटी अत्याचार(रोकथाम) कानून में संशोधन किया जाए, तब देश की जनता ने सड़कों पर उतरकर हिंदुत्व साजिश के खिलाफ अपना जबर्दस्त आक्रोश व्यक्त किया. उस मौके पर पुलिस गोलीबारी में 7 लोगों की जानें गयीं. जनता के आक्रोश की लपटों को देखकर केंद्र सरकार ने यह हामी भरी कि तुरंत वैसा कुछ नहीं होगा. उसके बाद फरवरी, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने जब यह आदेश जारी किया कि जिन आदिवासियों, परंपरागत वनवासियों(गैर–आदिवासियों) के पास वनाधिकार पट्टा नहीं है उन्हें उनकी जमीनों से बेदखल किया जाएगा, तब समूचा देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ आदिवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष में उतरा. इससे केंद्र सरकार को उक्त आदेश के अमल पर रोक लगानी पड़ी. ये सभी जीतें यही फैसला दे रही हैं कि संघर्षों के जरिए ही समस्याओं का हल निकाल सकते हैं. देश के मूलवासी विस्थापन के खिलाफ, जंगलों को बचाने के विशाल दृष्टिकोण के साथ उसी संघर्ष की राह पर आगे बढ़ रहे हैं. 'खदान नहीं, अनाज चाहिए', नारे के साथ जल–जंगल–जमीन के लिए एक ओर जनता आंदोलनरत है तो दूसरी ओर सरकारों द्वारा जंगलों को पुलिस छावनी बनया जा रहा है. इस तरह यह जनता के अस्तित्व की समस्या बन गया है. दंडकारण्य, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना सहित कई राज्यों के आंदोलनरत इलाकों की जनता प्रधानतया मूलवासी जनता नए पुलिस कैंपों के खिलाफ अपने संघर्षों को तेज कर रही है. आज देश की जनता के सामने यह आवश्यक बन गया है कि वह सरकारों की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ, मूलवासियों के जीवन–मरण के संघर्षों के समर्थन में डटे रहे.

संघर्षों के जरिए अपनी समस्याओं का हल करने वाले किसानों, दलितों, आदिवासियों की ही राह पर देश के मजदूर वर्ग को भी आंदोलन के लिए कमर कसना होगा. 40 कानूनों को चार संहिताओं में बदलकर उनके अधिकारों का हनन करने वाली मोदी सरकार के खिलाफ समझौताविहीन संघर्ष करने हमारी पार्टी मजदूरों का आह्वान करती है. देश के किसानों के समर्थन में डटे रहनेवाली जनता को अब मजदूरों के पक्ष में और भी दृढ़ता के साथ खड़े रहना चाहिए. ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए जनविरोधी, संविधानविरोधी सीएए कानून को रद्द कराने देश की जनता को फिर एक बार आगे आना होगा. कॉरपोरेट घरानों के सुलभ व्यापार (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के लिए 1,400 कानूनों को रद्द करने वाली केंद्र सरकार देश की जनवादी ताकतों एवं सवाल करने वाली आवाजों को दबाने के लिए औपनिवेशिक काल के राजद्रोह (सेडिशन एक्ट) कानून, निरंकुश गैर–कानूनी गतिविधि(निरोधक) कानून (युएपीए) का उपयोग कर रही है. उन कानूनों को तत्काल रद्द करने, किसान आंदोलनकारियों पर लगाए गए सभी मुकदमों को वापस लेने की मांगों को लेकर आंदोलित होना चाहिए. आज देश हिंदुत्व शक्तियों के महा खतरे का सामना कर रहा है. उसके खिलाफ सभी उत्पीड़ित वर्गों, विशेष सामाजिक तबकों, क्रांतिकारी जन संगठनों, मजदूर संगठनों,

वामपंथी पार्टियों सहित साथ आने वाले सभी के साथ एकजुट होकर सभी क्षेत्रों में जन समस्याओं के हल के लिए जुझारू संघर्ष अपनाना चाहिए.

हमारी पार्टी किसानों को सावधान करती है कि वे प्रधान मंत्री मोदी की हालिया घोषणा पर पूरी तरह भरोसा कर धोखे का शिकार न होवें. संसद में कानूनी प्रक्रिया के जरिए तीन कृषि कानूनों को रद्द करने तक संघर्ष में डटे रहे. पिछले साल भर के आंदोलन के दौरान जिन किसानों की जानें गयीं, उन सभी के परिवारों को एक–एक करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग करें. हमारी पार्टी यह आगाह करना चाहती है कि सिर्फ तीन कृषि कानूनों के रद्द से ही किसानों की सभी समस्याएं हल नहीं होंगी. हमारे देश में किसानों की आत्महत्याओं को रोकने, विगत तीन दशकों से किसान जिन समस्याओं का सामना करते आ रहे हैं, उनके अंतिम हल के लिए आवश्यक है कि वे वर्तमान संघर्ष स्फूर्ति के साथ ही मजदूर वर्गीय नेतृत्व में और भी जुझारू संघर्षों के लिए तैयार हो जाएं. कृषि प्रधान हमारे देश की जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए कृषि क्रांति को सफल बनाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है. ब्राह्मणीय हिंदुत्व शक्तियों के नया भारत के सपनों को चकनाचूर किए बगैर देश की जनता के लिए असली शांति, धर्मनिरपेक्षता, जनवाद, आत्मनिर्भरता तिनके के बराबर भी नहीं बचेंगी.

- 26 नवंबर को देश भर में ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी ताकतों के खिलाफ विजय दिवस मनावें.
- देश भर के क्रांतिकारी जन संगठनों, पीएलजीए को चाहिए कि वे किसानों की वर्तमान जीत को ऊंचा उठाते हुए उन्हें उनकी मूलभूत समस्याओं पर संगठित आंदोलनों में गोलबंद करें.
- देश में ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासवादी शासक वर्गों के नया भारत की नीतियों के किसी भी रूप में अमल को रोकेंगे.

- साम्राज्यवादियों, दलाल नौकरशाही पूंजीपति एवं सामंती वर्गों के शोषण के खिलाफ भारत की नवजनवादी क्रांति की जीत के लिए संघर्ष करेंगे.

अभय

(अभय)
प्रवक्ता,
केन्द्रीय कमेटी,
भाकपा (माओवादी)